बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 219 ● नई दिल्ली ● बुधवार 17 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

वैकेशन में कम हुई इलेक्ट्रिक डबल-डेकर टूरिस्ट बस के टिकट की कीमत, इतने हजार यात्रियों ने किया सफर

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक डबल-डेकर पर्यटक बस को मिल रही अच्छी प्रतिक्रिया के बीच पर्यटन विभाग ने गर्मी के मौसम में टिकट की कीमतें कम कर दी हैं. लॉन्च के बाद से अब तक यह बस 1,540 से अधिक यात्रियों को राजधानी के प्रमुख स्थलों की सैर करा चुकी है. अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वयस्कों का टिकट 500 रुपये से घटाकर 300 रुपये और बच्चों का टिकट 300 रुपये से घटाकर 200 रुपये कर दिया गया है. विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस ऑफर का जवाब काफी उत्साहजनक रहा है, खासकर वीकेंड पर सवारियां बढ़ी हैं. 28 फरवरी को शुरू हुई सेवा के पहले महीने में करीब 800 यात्री आए, तीन महीनों में यह संख्या 1,200 को पार कर गई.

दिल्ली-एनसीआर में आज फिर बारिश, गर्मी से मिली राहत; कैसे रहेगा एक सप्ताह तक मौसम?

नई दिल्ली ।

पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आखिरकार सोमवार दोपहर से राहत मिलनी शुरू हुई। नोएडा गुरुग्राम, राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मंगलवार को हुई झमाझम बारिश ने मौसम को पूरी तरह से सुहावना बना दिया है। इस बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को चिलचिलाती धूप से निजात मिली है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह तक प्री मानसून की बारिश की संभावना नहीं है, ऐसे में 21 जून तक तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, राजधानी में सोमवार को न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। यह सामान्य से .7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी ओर, सुबह से ही कड़ी धूप ने राजधानीवासियों को परेशान किया।

दोपहर में मौसम ने करवट ली और बादल छा गए। इस दौरान लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। आंधी के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में कमी आई। दोपहर में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी आई। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में अगले एक सप्ताह तक मौसम में अधिक बदलाव नहीं होगा। कहीं-कहीं हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी लेकिन, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने से लोगों को गर्मी परेशान करेगी। 20 से 21 जून तक न्यूनतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। नोएडा में मंगलवार सुबह मौसम साफ रहा और तेज धूप देखने को मिली, लेकिन करीब 7 बजे अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाओं और आंधी के साथ शुरू हुई बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया। सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई बारिश का दौर कई क्षेत्रों में जारी रहा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई प्रमुख मार्गों और चौराहों पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला, जिससे कार्यालय जाने वाले लोगों की रफ्तार धीमी पड़ गई। मौसम विभाग के अनुसार दिनभर रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है। विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भी बारिश और बादलों की आवाजाही का पूर्वानुमान जताया है। गुरुग्राम में हुई झमाझम बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। शहर के कई हिस्सों में, विशेष रूप से बस स्टैंड रोड पर, जलभराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया

नई दिल्ली ।

अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के बाद संभवत पहली बार प्रतिक्रिया दी. पणजी पणजी में जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे इस दौरान उनसे इसको लेकर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने बस इतना कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था. बीते अप्रैल महीने में आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से सात, जिनमें राघव चड्ढा भी शामिल थे, बीजेपी में शामिल हो गए. अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में टूट पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी असल में एक अनैतिक पार्टी है. लोग किसी पार्टी को वोट देते हैं लेकिन बीजेपी या तो बहुत सारा पैसा देकर विधायकों को खरीद लेती है या फिर पार्टियों को तोड़ने के लिए ईडी को भेजती है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो महाराष्ट्र और बंगाल में हुआ ये हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है. उन्होंने कहा, बीजेपी जो कर रही है, राजनीतिक दलों को तोड़ रही है, विपक्ष को कमजोर कर रही है, ईडी और पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है. हर एक को इसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, इसके आगे उन्होंने कहा, जो हो रहा है वो गलत है. लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया और 28 या 29 सांसद चुने. क्योंकि उन्हें पार्टी पर भरोसा था. इसके बाद उनमें से 20-22 अलग हो गए और किसी पार्टी को समर्थन दे दिया, ये तो सरासर गलत है. गोवा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रमोत सावंत की सरकार को बिजली से जुड़ी आप की मांगों को लागू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि गोवा के लोगों को भारी बिजली बिल भरना पड़ता है. ऐसे में यहां की सरकार को लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देनी चाहिए और 15 जून 2026 तक के सारे बिल माफ कर देने चाहिए. उन्होंने दावा किया कि इन दो मांगों को पूरा करती है तो यहां की 76 फीसदी आबादी के बिजली बिल जीरो आने शुरू हो जाएंगे.

'ईडी पार्टी' लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है, एजेंसी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है - संजय सिंह

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 16 जून मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय पर तीखा हमला बोला. उन्होंने ईडी को 'ईडी पार्टी' करार देते हुए आरोप लगाया कि यह एजेंसी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर राजनीतिक दलों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है. संजय सिंह ने कहा, जैसा कि हम बार-बार कहते रहे है, इस देश में एक 'ईडी पार्टी' है, जिसकी पूरी जिंदगी ईडी पर टिकी है. यही ईडी पार्टी ईडी के जरिए पूरे देश में लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उन्हें जेल भेजा. अब जब कुछ नहीं मिल रहा तो आप नेताओं को कायरतापूर्ण तरीके से निशाना बनाया जा रहा है.

दीपक सिंघला को निशाना बनाया जा रहा

संजय सिंह ने कहा कि गोवा में आप के को-इन-चार्ज दीपक सिंघला को बिना वजह निशाना बनाया जा रहा है. 2014 में उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज केस की जांच पूरी हो चुकी थी, चार्जशीट दाखिल हो गई और ट्रायल भी लगभग पूरा हो चुका है. इसके बावजूद उन पर लगातार रेड और गिरफ्तारियां हो रही हैं.

ईडी राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार

सिंह ने अशोक मित्तल के यहां श्च्छ की रेड का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें ले जाने से पहले परिसर को तोड़ दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी पार्टी और उसके प्रमुख बिना किसी ठोस वजह के आप नेताओं को परेशान कर रहे हैं. संजय सिंह ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने और विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या श्च्छ केवल विपक्षी दलों के खिलाफ ही सक्रिय है?

बार-बार पेपर लीक से नाराज प्रियंका गांधी, बोलीं- व्यवस्थागत सुधार की है तुरंत जरूरत

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बार-बार परीक्षा के पेपर लीक होने से प्रभावित छात्रों के प्रति एकजुटता जताई और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से अपील की कि वे छात्रों और उनके परिवारों की मुश्किलों को समझें। 16 जून को इस मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी, जिनकी सार्वजनिक जिम्मेदारी है, हमें छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वे किस तरह की मुश्किलों और तकलीफ़ों से गुज़रे हैं। हर पेपर लीक हो जाता है। उनके माता-पिता उनके लिए कर्ज़ ले रहे हैं। गांधी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह समस्या अलग-थलग नहीं है, बल्कि एक गहरी व्यवस्थागत समस्या का संकेत है जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एक गहरी व्यवस्थागत समस्या है, और हमें इसे मिलकर हल करना चाहिए। पेपर लीक कोई एक बार की समस्या नहीं है; यह बनी हुई है। हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। कांग्रेस नेता ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, ताकि छात्रों का भरोसा बहाल हो सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लगातार हो रही अनियमितताओं की वजह से उनकी मेहनत बेकार न जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, युवाओं से जुड़े मुद्दों और कथित परीक्षा घोटालों के खिलाफ कांग्रेस के अभियान के तहत, पूरे भारत में बड़े छात्र सम्मेलनों की एक श्रृंखला का नेतृत्व करेंगे। इसकी शुरुआत 17 जून को कोटा से होगी। कांग्रेस के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने घोषणा की कि आगे के कार्यक्रम 10 जुलाई को इलाहबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में छात्र, नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार, युवा संगठन और शिक्षक एक साथ आएंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी बड़े छात्र सम्मेलनों की एक सीरीज़ करेंगे, जिसकी शुरुआत कोटा (17 जून), इलाहबाद (10 जुलाई), पटना (11 जुलाई) और दिल्ली (14 जुलाई) से होगी। इन सम्मेलनों में छात्र, परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा, युवा संगठन, शिक्षक और वे सभी लोग शामिल होंगे जो परीक्षा से जुड़े घोटालों से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।

दिल्ली के शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के पास फैक्ट्री में भीषण आग, पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली के उत्तर-पश्चिम इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां केशवपुरम इलाके में स्थित शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के पास मंगलवार (16 जून 2026) को दोपहर में एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर से पूरे इलाके में अफरा-तफरी और हड़कंप का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि समय रहते दमकल विभाग को सूचना दे दी गई जिससे एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि डीएफएस को दोपहर करीब एक बजे आग लगने की सूचना मिली जिसके बाद दमकल की सात गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि दोपहर ढाई बजे तक आग को बुझा दिया और अब स्थान को ठंडा करने का अभियान जारी है।

गंदे पानी ने बढ़ाई बीमारी की चिंता, पेयजल संकट गहराया, व्यवस्था सुधारने की उठी मांग

नई दिल्ली । दिल्ली में भीषण गर्मी के साथ पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। उत्तम नगर, नजफगढ़, द्वारका में समेत कई इलाकों में लोगों को या तो समय पर पानी नहीं मिल रहा है या फिर जो पानी उपलब्ध हो रहा है, वह इतना गंदा और बदबूदार है कि उसका घर में उपयोग करना मुश्किल है। दूषित पानी की शिकायतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी पैदा किए हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि राजधानी की अधिकांश जलापूर्ति पाइपलाइनें कई दशकों पुरानी हो चुकी हैं। समय के साथ और इनमें जंग लगने के कारण जगह-जगह रिसाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। कई इलाकों में सीवर लाइन और पेयजल पाइपलाइन बेहद नजदीक बिछी होने के कारण दोनों में लीकेज होने पर सीवर का पानी पेयजल में मिल जाता है, जिससे पानी दूषित हो जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि दूषित पानी के सेवन से जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, ऐसे में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनका कहना है कि समस्या नई नहीं है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। नई दिल्ली। यमुनापार के कई इलाकों में पिछले करीब दो माह से पेयजल संकट गहराता जा रहा है। कहीं पानी की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही तो कहीं नलों से दूषित और दुर्गंधयुक्त पानी आने की शिकायतें मिल रही हैं। हालात ये हैं कि लोगों को पीने के पानी से लेकर रोजमर्रा के घरेलू कामकाज तक के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भजनपुरा, खजूरी खास, सोनिया विहार, यमुना विहार, वेस्ट ज्योति नगर, ईस्ट विनोद नगर और घोंडा समेत कई क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि कई इलाकों में पानी का दबाव इतना कम है कि बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों तक पानी नहीं पहुंच पाता, इससे परेशानी होती है। सुबह कुछ समय के लिए पानी आता है, थोड़ी देर बाद उसका रंग और गंध बदल जाती है।

राजनाथ सिंह के घर आधी रात तक बीजेपी-आरएसएस नेताओं ने किया मंथन, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई सूची तैयार

नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई लंबी बैठक के बाद अब पार्टी संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर बड़े बदलावों की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई करीब चार घंटे लंबी बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी अरुण कुमार और शिव प्रकाश शामिल रहे। यह बैठक देर रात तक चली और इसके बाद से यह माना जा रहा है कि भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कभी भी की जा सकती है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी-7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद ही अंतिम घोषणा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार भाजपा संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी पूरी हो चुकी है। केवल संगठन ही नहीं, बल्कि राज्यपालों की नियुक्तियों और सरकार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की भी संभावना जताई जा रही है। पार्टी के भीतर यह चर्चा है कि अधिक मास की अवधि समाप्त होने के बाद अब धार्मिक दृष्टि से भी ऐसे निर्णयों में कोई बाधा नहीं रह गई है। इसलिए संगठनात्मक और प्रशासनिक बदलावों की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है। हम आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम को लेकर पार्टी में काफी उत्सुकता है। बताया जा रहा है कि नई टीम में ग्यारह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छह राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा सकते हैं। पार्टी नेतृत्व इस बार जातीय और सामाजिक संतुलन पर विशेष ध्यान देने की तैयारी में है। महिला प्रतिनिधित्व को भी पहले से अधिक महत्व दिए जाने की संभावना है।

साथ ही युवा और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अगले वर्ष जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के नेताओं को भी संगठन में प्रमुख जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे चुनावी राज्यों के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी नेताओं को नई टीम में जगह मिलने की संभावना है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार जनवरी 2020 में जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद से राष्ट्रीय संगठन में बहुत कम बदलाव हुए हैं। ऐसे में यह फेरबदल आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी ने हाल के दिनों में संकेत भी देने शुरू कर दिए हैं। इसी महीने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुघ को राज्यसभा भेजा गया है। दोनों नेताओं को संगठन और चुनावी रणनीति में मजबूत माना जाता है। इनके साथ राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर और राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी उच्च सदन में भेजा गया है। इसे संगठन में व्यापक पुनर्संरचना की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर कुछ नेताओं के भविष्य को लेकर भी अटकलें तेज हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का राज्यसभा कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जार्ज कुरियन का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है और उनके स्थान पर नए चेहरों को अवसर दिए जाने की संभावना है। वरिष्ठ नेता अरुण सिंह भी नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

सम्पादकीय...

बढ़ता संकट

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चिंतित कर दिया है। सोमवार तड़के रूस द्वारा किए गए बड़े पैमाने के मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, 53 से अधिक लोग घायल हुए और लाखों लोगों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इस हमले की सबसे चिंताजनक बात यह रही कि इसकी चपेट में केवल सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि यूक्रेन की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरें भी आ गईं। राजधानी कीव स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रसिद्ध कीव-पेचेर्स्क लाव्रा मठ परिसर के डॉर्मिशन कैथेड्रल में लगी आग ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रूस ने रातभर मिसाइलों और कामिकाज़े ड्रोन की मदद से कई शहरों को निशाना बनाया। राजधानी कीव, खार्किव और अन्य प्रमुख शहरों पर हुए हमलों में आवासीय इमारतें, ऊर्जा ढांचे और सांस्कृतिक संस्थान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए। लगभग 1.4 लाख घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे आम नागरिकों की परेशानियां और बढ़ गईं। इस हमले का सबसे प्रतीकात्मक और भावनात्मक असर कीव-पेचेर्स्क लाव्रा पर पड़ा। 11वीं शताब्दी में स्थापित यह मठ परिसर पूर्वी यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। द्नीप्रो नदी के किनारे स्थित यह परिसर सदियों से ईसाई श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थस्थल रहा है। यहां मौजूद भूमिगत गुफाओं का जाल 600 मीटर से अधिक लंबा है और यह यूक्रेन की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि एक रूसी कामिकाज़े ड्रोन ने सीधे डॉर्मिशन कैथेड्रल की छत पर हमला किया, जिससे लगभग 800 वर्ग मीटर क्षेत्र में आग फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि मठ के साधुओं और बचावकर्मियों को मानव श्रृंखला बनाकर धार्मिक प्रतीकों, प्राचीन मूर्तियों और बहुमूल्य धार्मिक अवशेषों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ऐतिहासिक भवन का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस हमले को रूस की युद्ध जारी रखने की मंशा का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल यूक्रेन पर हमला नहीं है, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और मानवता पर भी हमला है। जेलेंस्की ने जी-7 देशों से रूस पर और अधिक दबाव बनाने तथा यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की अपील की। विशेष रूप से उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाली आधुनिक रक्षा प्रणालियों की मांग की। हमले का असर केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं रहा। यूक्रेन के संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि प्रसिद्ध ओलेक्सांद्र दोवझेंको राष्ट्रीय फिल्म स्टूडियो भी हमले की चपेट में आ गया। स्टूडियो के मुख्य परिधान भंडार को भारी नुकसान पहुंचा और लगभग एक लाख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की वेशभूषाएं जलकर नष्ट हो गईं। यह नुकसान केवल आर्थिक नहीं, बल्कि यूक्रेन की सांस्कृतिक स्मृति और फिल्म इतिहास के लिए भी अपूरणीय माना जा रहा है। यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख मेट्रोपॉलिटन एपिफानियस प्रथम ने इस हमले को -मानवता, इतिहास और ईसाई धर्म के विरुद्ध अपराध- बताया। वहीं उप प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने कहा कि इस घटना ने रूस के तथाकथित धार्मिक और नैतिक मूल्यों की वास्तविकता को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। रूस के इस हमले की एक और भयावह घटना खार्किव शहर में सामने आई। यहां एक मिसाइल हमले के बाद लगी आग बुझाने पहुंचे आपातकालीन सेवा कर्मियों को दोबारा ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। इस तथाकथित -डबल-टैप- रणनीति में पहले हमला कर बचाव दल को मौके पर बुलाया जाता है और फिर उन पर दूसरा हमला किया जाता है। इस घटना में पांच बचावकर्मियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार ऐसे हमलों को अत्यंत गंभीर माना जाता है क्योंकि वे सीधे राहत और बचाव कार्यों को निशाना बनाते हैं। इस हमले का समय भी महत्वपूर्ण है। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलग-अलग फोन कॉल में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी। जेलेंस्की ने कहा कि बातचीत में शांति की दिशा में संभावित कदमों पर चर्चा हुई, जबकि क्रेमलिन के अनुसार पुतिन और ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के साथ-साथ ईरान से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। हालांकि, इन कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद रूस द्वारा किया गया यह हमला संकेत देता है कि युद्ध के मैदान में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस सैन्य दबाव बढ़ाकर संभावित शांति वार्ताओं में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। दूसरी ओर यूक्रेन अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने और अपनी वायु रक्षा क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह हमला एक बार फिर उस प्रश्न को सामने लाता है कि आधुनिक युद्धों में सांस्कृतिक विरासत और नागरिक ढांचे की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्थलों पर हमले केवल किसी एक देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि मानव सभ्यता की साझा धरोहर को भी खतरे में डालते हैं। जब ऐतिहासिक चर्च, संग्रहालय, पुस्तकालय और सांस्कृतिक संस्थान युद्ध का शिकार बनते हैं, तब नुकसान केवल वर्तमान पीढ़ी का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी होता है। कुल मिलाकर, रूस का यह ताजा हमला यूक्रेन युद्ध की भयावहता को एक बार फिर उजागर करता है। नागरिकों की मौत, सांस्कृतिक धरोहरों का विनाश, ऊर्जा ढांचे पर हमले और बचावकर्मियों को निशाना बनाना इस संघर्ष की गंभीरता को दर्शाते हैं। ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने चुनौती केवल युद्ध रोकने की नहीं, बल्कि मानवता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की भी है। आने वाले दिनों में जी-7 देशों और अन्य वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया इस संघर्ष की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

भारत-यूरोप संबंधों का नया अध्याय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा भारतीय कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में देखी जा रही है। वर्ष 1993 में चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के बाद स्वतंत्र राष्ट्र बने स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह यात्रा केवल एक औपचारिक राजनयिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत और मध्य यूरोप के देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री मोदी यूरोप दौरे के तहत फ्रांस से स्लोवाकिया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। राजधानी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक अधिकारियों ने पारंपरिक 'ब्रेड एंड सॉल्ट' समारोह के माध्यम से उनका अभिनंदन किया। यह स्लोवाकिया की पुरानी परंपरा है, जिसके तहत सम्मानित अतिथियों का स्वागत रोटी और नमक भेंट कर किया जाता है। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। भारत और स्लोवाकिया के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1993 में हुई थी, जब चेकोस्लोवाकिया दो स्वतंत्र देशों ड्ड चेक गणराज्य और स्लोवाकिया ड्ड में विभाजित हो गया था। तीन दशक से अधिक समय में दोनों देशों के संबंध लगातार विकसित हुए हैं, लेकिन किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा पहली बार हो रही है। यही कारण है कि इस दौरे को दोनों देशों के संबंधों में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से विस्तृत वार्ता की। दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप' के स्तर तक पहुंचाने की घोषणा की। यह केवल एक कूटनीतिक शब्दावली नहीं है, बल्कि इससे संकेत मिलता है कि दोनों देश अब व्यापार, रक्षा, तकनीक, ऊर्जा, शिक्षा, नवाचार और वैश्विक मंचों पर सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और स्लोवाकिया -साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य- के भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाएं बहुत व्यापक हैं और आने वाले वर्षों में यह संबंध नई उपलब्धियां हासिल कर सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह यात्रा विशेष महत्व रखती है। स्लोवाकिया यूरोप का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र माना जाता है, विशेषकर ऑटोमोबाइल निर्माण के क्षेत्र में। दुनिया के सबसे बड़े कार उत्पादन केंद्रों में से एक होने के कारण स्लोवाकिया भारत के लिए निवेश और तकनीकी सहयोग का आकर्षक साझेदार बन सकता है। दोनों देशों के बीच रेलवे विनिर्माण, ऑटोमोबाइल उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र भी इस यात्रा का प्रमुख केंद्र रहा। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत विकसित हो रहे रक्षा उद्योग को यूरोपीय देशों के साथ जोड़ने का प्रयास इस समझौते में दिखाई देता है। स्लोवाकिया की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों से जुड़ा है। स्लोवाकिया यूरोपीय संघ का सदस्य है और मध्य यूरोप में उसकी रणनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में भारत की यह पहल केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप के साथ व्यापक आर्थिक और राजनीतिक जुड़ाव की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अधिक प्रतिनिधिक और प्रभावी बनाने की जरूरत पर सहमति व्यक्त की गई। यह भारत की उस लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप है, जिसमें वह वैश्विक शासन व्यवस्था में विकासशील देशों की अधिक भागीदारी की वकालत करता रहा है। इस यात्रा की एक विशेष उपलब्धि तब सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत और स्लोवाकिया के बीच मजबूत होते संबंधों तथा वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका की मान्यता के रूप में देखा जा रहा है। यह किसी विदेशी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 33वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान बताया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा भारत की बहुआयामी विदेश नीति का हिस्सा है, जिसके तहत नई दिल्ली केवल बड़ी शक्तियों तक सीमित न रहकर यूरोप के छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के साथ भी अपने संबंध मजबूत कर रही है। इससे भारत को निवेश, तकनीक और वैश्विक समर्थन के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा केवल एक राजनयिक दौरा नहीं बल्कि भारत और मध्य यूरोप के बीच उभरती साझेदारी का प्रतीक है। व्यापार, रक्षा, तकनीक और वैश्विक सहयोग के क्षेत्रों में हुए समझौते आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा दे सकते हैं। यह यात्रा इस बात का भी संकेत है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपने प्रभाव का विस्तार करते हुए नए क्षेत्रों और नए साझेदारों की ओर बढ़ रहा है। यदि इन समझौतों और घोषणाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह यात्रा भारत-स्लोवाकिया संबंधों के इतिहास में एक

> **इस यात्रा की एक विशेष उपलब्धि तब सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत और स्लोवाकिया के बीच मजबूत होते संबंधों तथा वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका की मान्यता के रूप में देखा जा रहा है। यह किसी विदेशी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 33वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान बताया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा भारत की बहुआयामी विदेश नीति का हिस्सा है, जिसके तहत नई दिल्ली केवल बड़ी शक्तियों तक सीमित न रहकर यूरोप के छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के साथ भी अपने संबंध मजबूत कर रही है।**

डेंगू पर नियंत्रण के लिए सामुदायिक जागरूकता आवश्यक

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्वभर में लगभग 39 करोड़ लोग डेंगू वायरस से संक्रमित होते हैं। इनमें से लगभग 9 से 10 करोड़ लोगों में बीमारी के स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्तियों में कोई लक्षण विकसित नहीं होते। वर्तमान समय में डेंगू भारत सहित अनेक देशों के लिए एक गंभीर जनस्वास्थ्य चुनौती बन चुका है और कई क्षेत्रों में यह महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न कर चुका है। डेंगू एक वायरल संक्रामक रोग है, जो मादा एडीज एजिप्टि मच्छर के काटने से फैलता है। संक्रमित मच्छर के काटने के बाद वायरस रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। डेंगू वायरस के चार अलग अलग सीरोटाइप होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जीवन में एक बार डेंगू हो चुका है, तो दूसरी बार संक्रमण होने पर बीमारी अधिक गंभीर रूप ले सकती है और जटिलताओं की संभावना बढ़ जाती है। पिछले कुछ वर्षों में मौसम संबंधी बदलावों ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के प्रसार को बढ़ावा दिया है। बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, अधिक आर्द्रता तथा मौसम के असामान्य व्यवहार ने मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि वर्षा के बाद जमा होने वाला पानी मच्छरों के प्रजनन का प्रमुख स्रोत बनता है। वहीं गर्म और नम वातावरण में इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डेंगू के शुरुआती लक्षणों में अचानक तेज बुखार, तीव्र सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, मतली, उल्टी तथा भूख में कमी शामिल हैं। जोड़ों और मांसपेशियों में अत्यधिक दर्द होने के कारण इसे कभी कभी ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। सामान्यतः बुखार कुछ दिनों में उतर जाता है, लेकिन शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने में कई सप्ताह लग सकते हैं। बड़े बच्चों और वयस्कों में इसके लक्षण अक्सर अधिक स्पष्ट और गंभीर दिखाई देते हैं। अधिकांश मामलों में डेंगू सामान्य बुखार के रूप में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ रोगियों में यह डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसी गंभीर स्थितियों का रूप ले सकता है। ऐसी परिस्थितियों में रक्तस्राव, प्लेटलेट्स में तेजी से कमी तथा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। समय पर उपचार न मिलने पर यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, अव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था और बदलती जीवनशैली के कारण ग्रामीण तथा उपनगरीय क्षेत्रों में भी डेंगू के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य समय समय पर डेंगू के गंभीर प्रकोप का सामना करते रहे हैं। उपचार मुख्य रूप से लक्षणों को नियंत्रित करने और रोगी की स्थिति पर निगरानी रखने पर आधारित होता है। यही कारण है कि डेंगू के मामले में बचाव को सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। डेंगू की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि घर, कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों में मच्छरों को पनपने का अवसर न दिया जाए। पानी जमा होने वाले सभी स्थानों की नियमित सफाई की जानी चाहिए। फूलों के गमलों, कूलर, पानी की टंकियों, ड्रमों और अन्य जल संग्रहण पात्रों को समय समय पर साफ करना चाहिए तथा उनका पानी बदलते रहना चाहिए। जिन बर्तनों में पानी रखा जाता है, उन्हें हमेशा ढककर रखना चाहिए।

बौद्ध चिंतन, सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों का प्रामाणिक दस्तावेज

उमेश कुमार सिंह

भारतीय बौद्धिक परंपरा में बौद्ध धम्म केवल एक धार्मिक विचारधारा नहीं, बल्कि मानवता, करुणा, तर्कशीलता और सामाजिक समानता का व्यापक आंदोलन रहा है। आज जब समाज अनेक प्रकार की वैचारिक, सामाजिक और नैतिक चुनौतियों से गुजर रहा है, तब बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। ऐसे समय में लेखक कैलाश चन्द्रा की डायमंड पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक बौद्ध धम्म – उद्भव एवं विकास एक गंभीर, शोधपरक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कृति के रूप में सामने आती है। कैलाश चन्द्रा लंबे समय तक शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में शिक्षक रहे हैं और सामाजिक सरोकारों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। लेखक का साहित्यिक और सामाजिक अनुभव इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने केवल ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन नहीं किया, बल्कि बौद्ध धम्म के सामाजिक, दार्शनिक और मानवीय पक्षों को गहराई से समझने और पाठकों तक सरल भाषा में पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यापक संरचना है। लगभग दस अध्यायों में विभाजित यह ग्रंथ बुद्ध के समकालीन भारतीय समाज से लेकर आधुनिक विश्व में बौद्ध धम्म की प्रासंगिकता तक का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। लेखक ने बौद्ध धम्म को केवल धार्मिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन, लोकतांत्रिक चेतना और मानवीय मूल्यों के विकास के संदर्भ में भी समझाया है। पुस्तक का पहला अध्याय -बुद्ध के समकालीन भारतीय समाज- विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें लेखक ने तत्कालीन भारतीय समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि बुद्ध का उदय केवल धार्मिक घटना नहीं था, बल्कि वह एक व्यापक सामाजिक क्रांति का परिणाम था। जातिगत असमानता, कर्मकाण्ड, सामाजिक विषमता और वैचारिक जड़ता के बीच बुद्ध ने करुणा, समता और विवेक का मार्ग प्रस्तुत किया। लेखक ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स और अन्य विद्वानों के विचारों के माध्यम से उस युग की सामाजिक चेतना को प्रभावी ढंग से सामने रखा है। लेखक की भाषा विद्वत्तापूर्ण होते हुए भी सहज और प्रवाहपूर्ण है। यह पुस्तक शोधार्थियों और गंभीर पाठकों के लिए उपयोगी होने के साथ-साथ सामान्य पाठकों के लिए भी बोधगम्य बनी रहती है। पुस्तक में प्रयुक्त संदर्भ, ऐतिहासिक तथ्य और दार्शनिक विश्लेषण इसकी विश्वसनीयता को मजबूत बनाते हैं। विशेष रूप से बुद्ध के नैतिक आदर्श, संघ व्यवस्था, त्रिपिटक परंपरा और बौद्ध दर्शन की व्याख्या अत्यंत संतुलित और तथ्यपरक प्रतीत होती है। दूसरे और तीसरे अध्याय में लेखक ने सिद्धार्थ गौतम के जीवन, ज्ञान की खोज, तपस्या, बोधि प्राप्ति तथा चार आर्य सत्यों का विस्तार से विवेचन किया है।

इन अध्यायों में केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि मानवीय संघर्ष, वैचारिक जिज्ञासा और आत्मबोध की यात्रा को भी प्रमुखता दी गई है। लेखक यह स्थापित करने में सफल रहते हैं कि बुद्ध का दर्शन जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं का यथार्थवादी समाधान प्रस्तुत करता है। पुस्तक का चौथा अध्याय -धम्म-प्रचार- विशेष महत्व रखता है। इसमें बुद्ध द्वारा शोषित और निम्न वर्गों को संघ में स्थान देने, भिक्षुणी संघ की स्थापना, अंगुलिमाल जैसे व्यक्तियों के जीवन परिवर्तन तथा अशोक और कनिष्क के माध्यम से बौद्ध धम्म के प्रसार का सशक्त चित्रण किया गया है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि बुद्ध का धम्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं था, बल्कि सामाजिक समरसता और नैतिक पुनर्निर्माण का आंदोलन भी था। पांचवें अध्याय में त्रिपिटक और बौद्ध संगीतियों का जो विस्तारपूर्वक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, वह इस पुस्तक को विशेष रूप से अकादमिक महत्व प्रदान करता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक की संरचना, उद्देश्य और ऐतिहासिक महत्व का व्यवस्थित विवेचन पाठकों को बौद्ध साहित्य की गहरी समझ प्रदान करता है। यह भाग शोधार्थियों और बौद्ध अध्ययन के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। छठे और सातवें अध्याय में बौद्ध दर्शन तथा विश्व को बौद्ध धम्म की देन का गंभीर विश्लेषण किया गया है। लेखक ने अहिंसा, अनात्मवाद, प्रतीत्यसमुत्पाद, क्षणिकवाद और कर्मवाद जैसे जटिल दार्शनिक विषयों को सरल भाषा में समझाने का सराहनीय प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि बौद्ध धम्म ने भारतीय संविधान, आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों, शिक्षा, कला, स्थापत्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किस प्रकार प्रभावित किया।

पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि लेखक ने बौद्ध धम्म को आधुनिक संदर्भों से जोड़ने का प्रयास किया है।

अंतिम अध्यायों में आधुनिक विश्व में बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता, सामाजिक सहिष्णुता, मानसिक शांति, नैतिक राजनीति और वैश्विक मानवता जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा की गई है। आज के तनावग्रस्त और विभाजित समाज में यह विमर्श अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है। हालांकि कुछ स्थानों पर पुस्तक का अकादमिक स्वर सामान्य पाठकों को थोड़ा गंभीर लग सकता है, लेकिन विषय की प्रकृति को देखते हुए यह स्वाभाविक भी है। पुस्तक में उद्धृत संदर्भों और ऐतिहासिक व्याख्याओं को और अधिक व्यवस्थित फुटनोट या संदर्भ सूची के साथ प्रस्तुत किया जाता, तो इसकी शोधपरक उपयोगिता और बढ़ सकती थी। फिर भी समग्र रूप से यह कृति अपने उद्देश्य में सफल दिखाई देती है। कैलाश चन्द्रा ने इस पुस्तक के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि साहित्य और समाज सेवा का संबंध अत्यंत गहरा है। उनका लेखन केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों को जागृत करने का कार्य भी करता है। पुस्तक में बुद्ध के विचारों को आधुनिक सामाजिक संदर्भों से जोड़कर प्रस्तुत करना लेखक की वैचारिक परिपक्वता को दर्शाता है। बौद्ध धम्म – उद्भव एवं विकास केवल बौद्ध धर्म पर आधारित पुस्तक नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज, इतिहास, दर्शन और मानवीय चेतना के विकास की एक गंभीर यात्रा है। यह कृति पाठकों को बुद्ध के विचारों की मूल भावना से परिचित कराती है और साथ ही यह संदेश भी देती है कि करुणा, समानता, विवेक और नैतिकता ही किसी सभ्य समाज की वास्तविक आधारशिला हो सकते हैं। निस्संदेह यह पुस्तक बौद्ध अध्ययन, भारतीय इतिहास, सामाजिक चिंतन और दर्शन में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी, संग्रहणीय और विचारोत्तेजक कृति है। यह पुस्तक केवल एक साहित्यिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों को समर्पित एक महत्वपूर्ण वैचारिक दस्तावेज है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला- अवैतनिक घरेलू श्रम को मिली कानूनी मान्यता

वैश्विक स्तरपर भारतीय समाज में सदियों से गृहिणी को परिवार की धुरी माना जाता रहा है,किंतु विडंबना यह है कि जिस महिला के श्रम पर पूरा परिवार, समाज और अंततः राष्ट्र की सामाजिक संरचना टिकी होती है,उसी के कार्य को आर्थिक दृष्टि से कभी उचित मान्यता नहीं मिल सकी। घर की सफाई,भोजन बनाना, बच्चों का पालन-पोषण, बुजुर्गों की देखभाल,परिवार के स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना,घरेलू वित्तीय प्रबंधन करना तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखना ऐसे कार्य हैं जो किसी भी पेशेवर सेवा से कम नहीं हैं। इसके बावजूद इन कार्यों को काम के बजाय कर्तव्य या पारिवारिक जिम्मेदारी मान लिया गया। परिणामस्वरूप करोड़ों महिलाओं द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू श्रम को राष्ट्रीय आय,सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तथा आर्थिक उत्पादकता के पारंपरिक मापदंडों में स्थान नहीं मिल पाया।आधुनिक डिजिटल और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में भी किसी व्यक्ति के योगदान कामूल्यांकन प्रायः उसके वेतन,आयकर या बैंक खाते में आने वाली आय से किया जाता है,जबकि गृहिणी का श्रम अदृश्य रह जाता है।यही कारण है कि लंबे समय से महिला अधिकार संगठनों, अर्थशास्त्रियों और समाज शास्त्रियों द्वारा यह मांग उठाई जाती रही है कि घरेलू कार्य को आर्थिक मूल्य दिया जाए और गृहिणियों के योगदान को औपचारिक मान्यता प्रदान की जाए। इसी व्यापक सामाजिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जून 2026 को, यह निर्णय एसएलपी (सिविल) नंबर 33915 of 2025 से उत्पन्न 2026 आईएनएससी 634 के रूपमें एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दिया है जिसने गृहिणियों को केवल होममेकर नहीं बल्कि नेशन बिल्डरअर्थात राष्ट्रनिर्माता की संज्ञा देकर भारतीय न्यायिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह निर्णय केवल मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की उस सोच को चुनौती देता है जो महिलाओं के घरेलू श्रम को कमतर आंकती रही है। साथियों यह ऐतिहासिक निर्णय शिशुपाल- शिवराम- अदर्स वर्सेज सुरजीत एंड अदर्स मामलेमें 11 जून 2026 को सुनाया गया। यह मामला वर्ष 2001 में पंजाब में हुई एक सड़क दुर्घटना से संबंधित था, जिसमें एक गृहिणी की मृत्यु हो गई थी। मृतका के परिवार ने मुआवजे की राशि को अपर्याप्त बताते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अंततः मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन . कोटिश्वर सिंह की द्वि-न्यायाधीशीय पीठ ने की। यह निर्णय एसएलपी (सिविल) नंबर . 33915 सद्द 2025 से उत्पन्न 2026 आईएनएससी 634 के रूप में दर्ज है। न्यायालय ने न केवल मुआवजे को बढ़ाकर लगभग 62.77 लाख रुपए कर दिया बल्कि गृहिणियों के आर्थिक योगदान पर भी व्यापक टिप्पणियां की।अपने निर्णय में न्यायालय ने अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों में कहा कि गृहिणियां परिवार मेंयोगदान देती हैं।

वे राष्ट्र निर्माता हैं। वे राष्ट्र का निर्माण करती हैं। उनके योगदान का मूल्यांकन और मौद्रिक आकलन कैसे किया जाए, यही चुनौती है। न्यायालय ने यह भी आशा व्यक्त की कि अब होममेकर शब्द को नेशन बिल्डरके रूप में देखा जाएगा। यह टिप्पणी केवल एक भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी संवैधानिक और सामाजिक सोच थी। न्यायालय ने स्वीकार किया कि जिस महिला के श्रम के कारण परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर पाता है, उसका योगदान राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है।

साथियों इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने गृहिणी के अवैतनिक घरेलू श्रम कान्यूनतम आर्थिक मूल्य निर्धारित करते हुए कहा कि मोटर दुर्घटना दावों में मुआवजा निर्धारित करने के लिए गृहिणी की काल्पनिक मासिक आय (नोशनल मंथली इन्कम) कम से कम 30,000 रुपए प्रति माह मानी जाएगी। भारतीय न्यायिक इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी स्पष्टता के साथ गृहिणी के श्रम को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है। न्यायालय ने माना कि यदि वही कार्य बाजार से खरीदे जाएं तो उनके लिए रसोइया, देखभालकर्ता, शिक्षक, घरेलू प्रबंधक और परामर्शदाता जैसी अनेक सेवाओं का भुगतान करना पड़ेगा।

इसलिए यह कहना कि गृहिणी आय अर्जित नहीं करती,वास्तविकता के विपरीत है। साथियों, न्यायालय ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर अर्थात घरेलू देखभाल की हानि को मुआवजे की एक स्वतंत्र श्रेणी के रूप में मान्यता दी। पहले मोटर दुर्घटना मामलों में मुख्य रूप से आय की हानि, आश्रितों की हानि, चिकित्सा व्यय और अन्य पारंपरिक मदों के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाता था,लेकिन गृहिणियों के मामले में यह व्यवस्था अपर्याप्त थी क्योंकि उनकी कोई प्रत्यक्ष वेतन आय नहीं होती। न्यायालय ने कहा कि परिवार को मिलने वाली घरेलू देखभाल, बच्चों की परवरिश, पति-पत्नी के पारस्परिक सहयोग तथा परिवार के भावनात्मक और सामाजिक प्रबंधन का भी आर्थिक मूल्य है। इसलिए इसे अलग श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। साथियों, निर्णय की सबसे प्रभावशाली टिप्पणियों में से एक यह थी कि गृहिणी को डिपेंडेंट अर्थात आश्रित कहना विडंबनापूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि वास्तव में पूरा परिवार गृहिणी पर निर्भर रहता है। भारतीय न्यायिक विमर्श में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण परिवर्तन है।

पारंपरिक रूप से आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को परिवार का मुख्य आधार माना जाता रहा है, जबकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि घर की व्यवस्था,बच्चों का पालन- पोषण, बुजुर्गों की देखभाल और सामाजिक स्थिरता का वास्तविक आधार गृहिणी होती है। इसलिए उसे केवल आश्रित के रूप में देखना उसकी भूमिका को कम करके आंकना है।सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी माना कि महिलाओं का अवैतनिक श्रम भारतीय अर्थव्यवस्था की अदृश्य नींव है। न्यायालय ने पितृसत्तात्मक सोच की आलोचना करते हुए कहा कि लंबे समय से घरेलू कार्य को वास्तविक काम नहीं माना गया, जबकि यह समाज के पुनरुत्पादन और मानव संसाधन निर्माण की मूल प्रक्रिया है।

बच्चे का पालन- पोषण, बुजुर्गों की देखभाल,भोजन तैयार करना,परिवार का भावनात्मक संतुलन बनाए रखना और सामाजिक मूल्यों का हस्तांतरण, ये सभी कार्य आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। यदि ये कार्य न हों तो श्रम बाजार, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संरचना गंभीर रूप से गतिहीनता से प्रभावित हो जाएगी। साथियों, इस निर्णय का महत्व केवल मुआवजा कानून तक सीमित नहीं है। यह भारतीय समाज को यह संदेश देता है कि महिलाओं का घरेलू श्रम किसी वेतनभोगी नौकरी से कम नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वर्षों से अनपेड केयर इकॉनमी और केयर वर्क को मान्यता देने की मांग उठती रही है। संयुक्त राष्ट्र और अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने बार-बार कहा है कि महिलाओं का अवैतनिक श्रम आर्थिक विकास का आधार है, लेकिन राष्ट्रीय लेखांकन प्रणालियों में इसे पर्याप्त स्थान नहीं मिला है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय उसी वैश्विक विमर्श के अनुरूप दिखाई देता है। इस फैसले का एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रभाव यह होगा कि भविष्य में मोटर वाहन दुर्घटना मामलों में गृहिणियों के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की गणना का तरीका बदल जाएगा। अब बीमा कंपनियां और न्यायाधिकरण गृहिणी के योगदान को केवल सांकेतिक रूप से नहीं आंक सकेंगी। उन्हें न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करना होगा। इससे हजारों परिवारों को अधिक न्यायसंगत मुआवजा मिलने की संभावना है। साथियों, सामाजिक दृष्टि से भी यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2017/00863)

अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, परिवार में मचा कोहराम

नेबुआ नौरंगिया (कुशीनगर)। थाना क्षेत्र के सौराहा खुर्द गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान खैरटिया शीतलापुर निवासी खेदन कुशवाहा (60) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि किसी कार्य से जाते समय तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का इकलौता पुत्र मुंबई में मजदूरी करता है। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की तलाश में जुटी है तथा मामले की जांच कर रही है।

मोदी का सर्वाधिक कार्यकाल सुशासन व जनविश्वास की पहचान- सुरेंद्र कुशवाहा

पटहेरवा (कुशीनगर)।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने विभिन्न गांवों का भ्रमण कर लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे लंबा कार्यकाल देशवासियों के अटूट विश्वास, सुशासन और विकास की राजनीति की स्वीकृति का प्रमाण है।

विधायक ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि और निःशुल्क राशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। इस दौरान उन्होंने कई वरिष्ठजनों को अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अमलेश तिवारी सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

डाकघर राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ का 9वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

कुशीनगर। डाकघर राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत के 9वें स्थापना दिवस पर पडरौना में अभिकर्ताओं ने केक काटकर, मिठाई खिलाकर उत्सव मनाया तथा मुसहर बस्ती में बच्चों को मिष्ठान एवं फल वितरित किए। इस अवसर पर जिला संरक्षक प्रेम शंकर सिंह, अर्जुन जायसवाल, संजय मारोदिया, अरुण तुलस्यान, अशोक टीबड़ेवाल सहित अनेक वक्ताओं ने संगठन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पियूष सराफ, दीनबंधु गुप्ता, जयप्रकाश मद्धेशिया, मनीष यादव, सूरज जायसवाल, विवेकानंद दीक्षित, अंगद यादव, हरेंद्र वर्मा, पूनम अग्रवाल, सीमा तुलस्यान, रेखा टीबड़ेवाल सहित बड़ी संख्या में डाक अभिकर्ता उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, अधिक कीमत पर यूरिया बेचने के आरोप में किसान खाद भंडार समेत दो गोदाम सील

कुशीनगर। किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया बिक्री की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जटहां बाजार (विशुनपुरा) स्थित एक उर्वरक प्रतिष्ठान एवं उससे संबंधित दो गोदामों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान कुल 459 बोरी यूरिया बरामद हुई, जिन्हें प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार, किसानों द्वारा यूरिया की कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री किए जाने की शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष की गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक निबंधक एवं सहायक आयुक्त सहकारिता तथा जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने जटहां बाजार स्थित किसान खाद भंडार पर छापेमारी की। जांच के दौरान प्रतिष्ठान पर किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक, लगभग 300 रुपये प्रति बोरी की दर से यूरिया बेचने के आरोपों की पुष्टि होने पर अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान के साथ उससे संबंधित दो गोदामों को सील कर दिया। निरीक्षण में गोदामों में कुल 459 बोरी यूरिया का स्टॉक पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से उर्वरक कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं किसानों ने कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

तीन दशक पुराने अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 16 एकड़ सीलिंग भूमि कराई गई मुक्त

सीलिंग भूमि पर कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक टीम

निचलौल।

तहसील क्षेत्र के ग्राम गिरहिया में लगभग तीन दशक से करीब 16 एकड़ सीलिंग की भूमि पर कुछ लोग अवैध तरीके से कब्जा किया था। ऐसे में मंगलवार को प्रशासन ने इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीलिंग भूमि पर लगे गन्ने की फसल को तीन ट्रैक्टर से जोतकर खाली कराया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच रहा। इतना ही नहीं उक्त सीलिंग भूमि पर दोबारा कब्जा करने पर अधिकारियों की ओर से अवैध कब्जाधारियों को सख्त कार्रवाई के लिए चेतावनी भी दी गई है। एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि गिरहिया ग्राम प्रधान पूनम चौधरी की ओर से डीएम को शिकायती पत्र देकर गांव की सीलिंग भूमि पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे को हटवाने की मांग की गई थी। ऐसे में मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर भूमि को खाली कराने की कार्रवाई की है। तहसीलदार अमित कुमार सिंह ने बताया कि गांव में स्थित आराजी संख्या 107 रकबा 3.411 हेक्टेयर तथा आराजी संख्या 106 रकबा 2.886 हेक्टेयर सहित कुल करीब 16 एकड़ भूमि सीलिंग की घोषित सरकारी भूमि है। इस भूमि पर कुछ लोगों ने लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा कर खेती शुरू कर दी थी। वर्तमान में उक्त भूमि पर गन्ने की फसल भी लगा रखी थी।

प्रशासन द्वारा कई बार सूचना और चेतावनी दिए जाने के बावजूद कब्जाधारियों की ओर से भूमि को खाली नहीं की गई। इसके चलते यह कार्रवाई करनी पड़ी। इन्होंने आगे कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त सीलिंग भूमि को कब्जामुक्त कराने के साथ ही संबंधित लोगों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की कड़ी चेतावनी दी गई है। इस अवसर पर निचलौल थाना प्रभारी निरीक्षक अंकित सिंह, हल्का लेखपाल अनिल कुशवाहा, मनीष पटेल, भारतेंदु, उत्कर्ष समेत राजस्व विभाग और पुलिस के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

'सरकार आपके द्वार' से जनता की समस्याओं का होगा घर बैठे समाधान- दारा चौहान

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कसानगंज ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कारागार एवं कुशीनगर प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं एवं महिलाओं के हित में लगातार कार्य कर रही है। अब किसी पीड़ित को अपनी समस्या के समाधान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 'सरकार आपके द्वार' पहुंच चुकी है। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी वंदना श्रीवास्तव ने भी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए 11 स्टालों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख विशाल सिंह, खंड विकास अधिकारी अमरनाथ पांडेय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।

चंचरीक जी को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

हाटा (कुशीनगर)। स्थानीय श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में प्रो. जयप्रकाश नारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में स्वर्गीय त्रिलोकी त्रिपाठी चंचरीक की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। सभा में वरिष्ठ साहित्यकारों एवं कवियों ने चंचरीक जी के साहित्यिक, सामाजिक एवं मानवीय योगदान को याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने उन्हें साहित्य जगत का मार्गदर्शक, लोकधर्मी कवि तथा अनेक साहित्यकारों का अभिभावक बताया। इस अवसर पर लियाकत अली जौहर, एडवोकेट अब्दुल हमीद आरजू, डॉ. शैलेन्द्र असीम, चंदेश्वर परवाना, डॉ. घनश्याम तिवारी, कृष्णा श्रीवास्तव सहित अनेक साहित्यकारों ने अपने विचार व्यक्त किए। चंचरीक जी के ज्येष्ठ पुत्र अनिल कुमार त्रिपाठी ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. जयप्रकाश नारायण द्विवेदी ने चंचरीक जी को संदेश संस्था का आदिपुरुष बताते हुए उनकी स्मृति में स्मृति अंक एवं पुरस्कार शुरू करने का प्रस्ताव रखा। अंत में दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। संचालन सच्चिदानंद पांडेय ने किया।

साईं भक्तों को मिलने जा रहा है नई रेल सेवा विशेष उपहार, पुणे से साईनगर शिर्डी के बीच जल्द शुरू होगी नई रेल सेवा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे-साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी

गोरखपुर । महाराष्ट्र के रेल यात्रियों और साईं भक्तों के लिए जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पहली बार पुणे से साईनगर शिर्डी के बीच सीधी एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है। पुणे-साईनगर शिर्डी नई रेल सेवा से पुणे, अहिल्यानगर और शिर्डी क्षेत्र के लाखों यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को सीधी रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा तथा क्षेत्रीय संपर्क, धार्मिक पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण इस नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह रेल सेवा महाराष्ट्र के प्रमुख शहरी एवं धार्मिक केंद्रों को सीधे जोड़ते हुए यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का नया विकल्प प्रदान करेगी। पुणे और साईनगर शिर्डी के बीच संचालित होने वाली यह नई रेल सेवा पुणे, श्रीगोंदा रोड, अहिल्यानगर जंक्शन, राहुरी और बेलापुर होते हुए साईनगर शिर्डी पहुंचेगी। इस रेल सेवा से पुणे और शिर्डी के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सीधा रेल संपर्क मिलेगा जिससे श्रद्धालु अब एक ही दिन में शिर्डी दर्शन कर पुणे वापस भी आ सकेंगे। अहिल्यानगर क्षेत्र के यात्रियों को भी इस सेवा से विशेष लाभ मिलेगा। नई रेल सेवा के माध्यम से पुणे और शिर्डी दोनों दिशाओं में आवागमन अधिक सुविधाजनक होगा। धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ शिक्षा, रोजगार, व्यापार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को भी बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध होगी। साईं बाबा के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को इस रेल सेवा से विशेष सुविधा मिलेगी। पुणे, अहिल्यानगर तथा आसपास के क्षेत्रों से शिर्डी तक सीधी रेल यात्रा उपलब्ध होने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पुणे-साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस का शुभारंभ महाराष्ट्र में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह नई रेल सेवा पुणे और शिर्डी के बीच संपर्क को सशक्त बनाते हुए लाखों श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक सुगम बनाएगी तथा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता, विकास योजनाओं की जनपद स्तरीय रिपोर्ट जारी

देवरिया।

केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को विकास भवन के गांधी सभागार में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विकास बैंक के पूर्व सभापति संतराज यादव ने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, नीतियों और विकासपरक कार्यक्रमों का विस्तृत जनपद स्तरीय लेखा-जोखा प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदला है, जिसका सीधा विधिक लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे शोषित, वंचित और असहाय वर्ग को मिला है। यह कार्यकाल जनविश्वास और सुशासन की नीतियों को धरातल पर उतारने का रहा है।

प्रेस वार्ता में डिजिटल गवर्नेंस की सफलता को रेखांकित करते हुए बताया गया कि पारदर्शी व्यवस्था और सीधे बैंक खातों में धनराशि (डीबीटी) भेजने की विधिक प्रक्रिया से देश में 4.31 लाख करोड़ रुपये

गलत हाथों में जाने से रोके गए हैं। सरकार की विभिन्न नीतियों के कारण देश के लगभग 25 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जहां जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक खाते खोले गए और 60 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, वहीं ग्रामीण अंचलों में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान, 11 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन और 16 करोड़ घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में लखपति दीदी और सुकन्या समृद्धि योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। स्थानीय विकास और उपलब्धियों की बात करें तो वर्ष 2014 से अब तक अकेले देवरिया जनपद में 7,74,334 आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5,46,509 महिला लाभार्थियों को 74.32 करोड़ रुपये की विधिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। शिक्षा विभाग के माध्यम से 10,12,329 छात्रों को डीबीटी के जरिए 117.26 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 1,07,506 और निराश्रित महिला पेंशन में 63,702 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22,448 ग्रामीण आवास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 4,20,695 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में 30 बेडेड ट्रॉमा सेंटर और सलेमपुर अग्निशमन केंद्र जैसी बड़ी प्रशासनिक ढांचागत परियोजनाएं जनपद के सर्वांगीण विकास को गति दे रही हैं। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष काली प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा, अजय दुबे, अबिकेश पांडेय और प्रभाकर तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जनपद में पौने आठ लाख आयुष्मान कार्ड, जननी सुरक्षा और डीबीटी के जरिए करोड़ों का वित्तीय हस्तांतरण

पाकिस्तान से पंजाब और फिर दिल्ली तक - आईएसआई आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, बड़े हमले की साजिश नाकाम; सात गिरफ्तार

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान समर्थित एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी-अपराध सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। यह सिंडिकेट गैंगस्टर से आतंकवादी बने शाहजाद भट्टी और अजमल गुर्जर द्वारा संचालित था। इस कार्रवाई में सात प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में कई आतंकी घटनाओं की योजना को विफल कर दिया।

हथियार और कारतूस बरामद

स्पेशल सेल की पूर्वी रेंज की टीम ने यह सफलता हासिल की। इंस्पेक्टर राहुल कुमार, विनीत कुमार तेवतिया और अजीत कुमार ने टीम का नेतृत्व किया। एसीपी कैलाश सिंह बिष्ट की देखरेख में यह अभियान चला। सिंडिकेट पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते दिल्ली और एनसीआर में अवैध हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पांच अत्याधुनिक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल मिलीं। साथ ही 41 जिंदा कारतूस, सात मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो वाहन भी बरामद हुआ। मोबाइल फोन में शाहजाद भट्टी और अजमल गुर्जर से जुड़ी आपत्तिजनक चैट और वॉयस नोट थे। स्पेशल सेल के समय पर हस्तक्षेप से आईएसआई प्रायोजित छद्म युद्ध को बड़ा झटका लगा है।

गिरफ्तार आरोपी और बरामदगी

गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों में अनस, मोहित, दीपक, आरिफ, करणवीर सिंह, जतन और साबिर शामिल हैं। अनस, मोहित, आरिफ और साबिर गाजियाबाद के लोनी के निवासी हैं। दीपक और जतन गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी के रहने वाले हैं। करणवीर सिंह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का निवासी है। इनके पास से पांच पिस्तौल, 41 कारतूस, सात मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली। सिंडिकेट द्वारा मादक पदार्थों और अवैध हथियारों की बिक्री से प्राप्त आय के लिए कई बैंक खातों का विवरण भी मिला है।

आतंकी साजिश और संचालन

स्पेशल सेल को 2026 मई के मध्य में खुफिया जानकारी मिली थी। शाहजाद भट्टी और अजमल गुर्जर आईएसआई के इशारे पर दिल्ली-एनसीआर में हमले की योजना बना रहे थे। वे सोशल मीडिया से युवाओं को भर्ती कर रहे थे। सूचना पर मोहित को यमुना विहार, दिल्ली के पास पकड़ा गया, जिसके पास से एक पिस्तौल और मोबाइल फोन मिला। पूछताछ में अनस, आरिफ और करण जैसे साथियों की भर्ती का पता चला। उन्हें सार्वजनिक स्थानों की रेकी करने का निर्देश था, जिसका उद्देश्य भय फैलाना और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना था।

कार्यप्रणाली और संबंध

शाहजाद भट्टी और उसके विदेशी सहयोगी सोशल मीडिया का उपयोग करते थे। वे भारतीय युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करते थे, उन्हें पैसे का लालच देते थे। नेटवर्क एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन, डिस्पोजेबल मोबाइल नंबर और हवाला चैनलों से काम करता था। आरिफ ने अजमल गुर्जर से एक विदेशी पिस्तौल एक लाख रुपये में खरीदी, जिसका भुगतान यूपीआई स्कैनर से हुआ।

ममता ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों को कानूनी चुनौती दी है। इस सीट पर भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें शिकस्त दी थी। ममता बनर्जी ने इस चुनावी हार के खिलाफ हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की है। 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को अपने इस पुराने गढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने 15,105 मतों के अंतर से पराजित किया। इस अप्रत्याशित हार ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। इस चुनावी नतीजे के बाद से ही टीएमसी खेमे में भारी असंतोष और बेचैनी देखी जा रही है।

राम मंदिर चढ़ावा घोटाला- टिन्नू यादव के घर से करोड़ों का सोना जब्त, 50 करोड़ की बेनामी संपत्तियां भी पता चलीं

अयोध्या ।

रामनगरी अयोध्या स्थित राम मंदिर के खजाने और चढ़ावे में करोड़ों रुपये के गबन का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) 15 जून 2026 को अयोध्या पहुंची। टीम ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से छह घंटे तक पूछताछ की और डिजिटल साक्ष्य खंगाले। कार्रवाई से पहले, पांच मुख्य संदिग्धों से करीब दो करोड़ रुपये नकद, एक लग्जरी कार और तीन आईफोन बरामद हुए। इस घोटाले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी सहयोगी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का नाम सामने

आया है। 13 जून 2026 को टिन्नू के पैतृक आवास पर छापेमारी में भारी मात्रा में शुद्ध सोना जब्त किया गया। सूत्रों के अनुसार, इस सोने की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कई करोड़ रुपये हो सकती है। जांच में पता चला है कि टिन्नू के पास अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्तियां हैं। वह कभी ऑटो रिक्शा चलाता था। अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास उसका एक 70 कमरों वाला छात्र छात्रावास भी है। एसआईटी जल्द ही इस छात्रावास की भी जांच कर सकती है।

सोमेश आनंद और केडी तिवारी पर संदेह

सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर सोमेश आनंद भी आया है। वह मंदिर निर्माण के मुख्य प्रभारी गोपाल राय का कथित भतीजा बताया जा रहा है। सोमेश ने एक साल में देश के विभिन्न राज्यों की 50 से अधिक संदिग्ध यात्राएं की हैं। वह अयोध्या रेलवे स्टेशन से बोरों में भारी सामान भरकर ट्रेन से दक्षिण भारत जाता था। वापसी में वह हवाई जहाज से खाली हाथ अयोध्या लौटता था। फिलहाल सोमेश के बैंक खातों और हवाई टिकटों की बारीकी से जांच की जा रही है।

आभूषणों की जिम्मेदारी और जमीन का सौदा

इस मामले में केडी तिवारी का नाम भी सामने आया है। उनके पास रामलला के आभूषणों को संभालने की मुख्य प्रशासनिक जिम्मेदारी थी। सुरक्षा अधिकारियों ने उनके आवास पर भी छापेमारी की थी। केडी तिवारी द्वारा हाल ही में खरीदी गई डेढ़ करोड़ रुपये की जमीन का सौदा जांच के दायरे में है। उन्होंने मीडिया से कहा, -मेरी ड्यूटी महज श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए आभूषणों को तौलकर उन्हें रसीद देने तक सीमित थी, उसके बाद मैं उसे ट्रस्ट के वरिष्ठों को सौंप देता था; आगे गहनों के साथ क्या खेल होता था, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा ट्रंप के साथ उठाएं प्रधानमंत्री- प्रियंका गांधी

नेशनल डेस्क ।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीन भारतीय नाविकों की मौत का विषय उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की एक हफ्ते की यात्रा पर हैं। वह फ्रांस में जी-7 सम्मेलन के संपर्क सत्र में हिस्सा लेंगे। उनका जी-7 सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी मुलाकात हो सकती है। इस बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि उन्हें निश्चित रूप से यह मुद्दा (अमेरिकी हमले में मारे गए तीन भारतीय नाविकों का

मामला) उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह हैरानी की बात है कि जो हो रहा है, उस पर हमने (सरकार) खुलकर कोई बात नहीं की है। अमेरिका ने बीते 10 जून को पलाऊ के ही ध्वज वाले जहाज सेंटेबेलो पर हमला किया था, जिसपर सवार 24 भारतीय नाविकों में से तीन की मौत हो गई थी।

खरगे ने टेलीग्राम बैन पर सरकार को घेरा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस

नई दिल्ली।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न मांगकर मोदी सरकार जवाबदेही की पहली परीक्षा में ही पूरी तरह फेल हो चुकी है।

खरगे ने आगामी 21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षण परीक्षा से ठीक पहले सरकार की ओर से मैसेजिंग एप टेलीग्राम पर लगाए गए प्रतिबंधों की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार टेलीग्राम ब्लॉक करने के बजाय शिक्षा मंत्री को पद से हटाए, जिन्होंने देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य ही ब्लॉक कर दिया है।

कांग्रेस प्रमुख ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे मुख्य आरोपियों

***माफिया को बचाने के लिए छोटे मोहरों पर कार्रवाई - खरगे**

***बदनामी के दौर में यूपीएससी और सीबीएसई- कांग्रेस अध्यक्ष**

को बचाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि वायुसेना की मदद लेना, टेलीग्राम पर रोक लगाना या फिर पेपर लीक माफिया को बचाने के लिए छोटे मोहरों को पकड़ना, मोदी सरकार की मजबूरी बन चुका है। खरगे ने चौंकाने वाले आंकड़े साझा करते हुए दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में देश के भीतर कुल 90 पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस महाघोटाले और भ्रष्टाचार के कारण देश के लगभग नौ करोड़ युवाओं को मानसिक और आर्थिक रूप से भुगतना पड़ रहा है।

नीट-पेपर लीक पर संग्राम

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि वह कब तक अपनी इन भारी विफलताओं पर पर्दा डालती रहेगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने इन अनियमितताओं के दर्दनाक नतीजों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा में हो रही धोखाधड़ी से हताश होकर करीब आधा दर्जन युवा आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के माता-पिता कर्ज लेकर बरसों तक परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, लेकिन अंत में नीट , एसएससी , यूजीसी-नेट और सीयूईटी जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि सीबीएसई के नतीजों में भी बड़ा खेल हुआ, जिसे खुद होनहार छात्रों ने उजागर किया। अब देश में विश्वसनीयता का अंतिम प्रतीक मानी जाने वाली यूपीएससी परीक्षा पर भी गंभीर आरोप लगने लगे हैं।

राहुल गांधी संभालेंगे मोर्चा

नीट पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली और सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग में हुए विवाद को लेकर कांग्रेस लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। अब इस लड़ाई को और धार देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद मैदान में उतरने जा रहे हैं। राहुल गांधी 17 जून से राजस्थान के कोटा शहर से देशभर में छात्र सम्मेलनों को संबोधित करने की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश के छात्र समुदाय को एकजुट करना और मोदी सरकार को इस मोर्चे पर पूरी तरह घेरना है।

कोटा में राहुल की एंट्री से पहले सियासी संग्राम, 19 पेपर लीक वाले पोस्टरों से मचा बवाल

कोटा । । कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोटा दौरे से पहले अब सियासत की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर शहर में लगे राहुल गांधी के पोस्टर हटाने का आरोप लगाया है। बुधवार को राहुल गांधी कोटा के दशहरा मैदान में संवाद कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वह छात्रों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और परीक्षा से पहले छात्रों को मोटिवेट करेंगे। जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से शहर के प्रमुख चौराहों और मुख्य मार्गों पर राहुल गांधी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर आरोप-प्रत्यारोपों की भी सोशल मीडिया पर झड़ी लग गई है। राहुल गांधी के कोटा दौरे से पहले कांग्रेस ने जहां पूरे शहर में पोस्टर लगा दिए हैं, वहीं इन्हीं पोस्टरों के बीच कई ऐसे पोस्टर भी लगा दिए गए हैं, जिन्होंने राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। शहर के जवाहर नगर, तलवंडी, महावीर नगर सहित कई जगहों पर कांग्रेस के पोस्टरों के बीच कांग्रेस के खिलाफ लगे पोस्टर भी चर्चा का विषय बन गए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है कि जिनके खुद के राज में 19 पेपर लीक हुए, वे किस मुंह से विद्यार्थियों से संवाद करेंगे? ऐसे में कोटा इन राजनीतिक दलों के लिए अखाड़े का मैदान बन गया है, जहां जुबानी हमलों के साथ पोस्टर वॉर भी लगातार जारी है।

पोस्टर हटाने के आरोप पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला

कोटा शहर में लगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पोस्टर हटने पर अब विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राहुल गांधी के आने से पहले ही भाजपा में डर बैठ गया है।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोटा में राहुल गांधी के पोस्टर और होर्डिंग यदि सोची-समझी साजिश के तहत हटाए जा रहे हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है। कोई नेता किसी भी शहर में जाता है तो उसका स्वागत होता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। इस तरह होर्डिंग नहीं उतारने चाहिए। भाजपा यही काम करती है। उन्हें राहुल गांधी के कोटा दौरे से डर लगने लगा है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं।

जो जाना चाहते हैं जाएं - उद्धव ठाकरे का ऑपरेशन टाइगर पर कड़ा संदेश, महाराष्ट्र में उबाल

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के कथित ऑपरेशन टाइगर को लेकर अटकलें जारी हैं। इस बीच, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सांसदों के साथ बैठक में मजबूती दिखाने की कोशिश की, जबकि दोनों गुटों के नेता घटनाओं के बारे में बिल्कुल अलग-अलग बातें कह रहे हैं। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार, ठाकरे ने सांसदों से कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वे आजाद हैं और वे उनके अच्छे भविष्य की ही कामना करेंगे। 2022 में हुई बगावत, जिससे शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई थी, उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्हें इन घटनाक्रमों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने किसी पर भी

पार्टी में बने रहने के लिए दबाव नहीं डाला। ठाकरे ने सांसदों से कहा कि चार साल पहले पार्टी में बड़ी टूट हुई थी। चालीस विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे। क्या आपको लगता है कि मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है? कहा जाता है कि उन्होंने यह भी कहा था कि जिन लोगों ने बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना छोड़ी है, उन्हें आखिरकार अपने फैसले पर पछतावा होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि आज मेरा समय न हो, लेकिन कल जरूर मेरा समय आएगा। तब तक हमें डटे रहना होगा और हिम्मत बनाए रखनी होगी। हालांकि, आज दिल्ली में शिवसेना सांसद संजय राउत ने उन खबरों का कड़ा विरोध किया जिनमें कहा गया था कि ठाकरे ने नेताओं से कहा था कि वे चाहें तो पार्टी छोड़ सकते हैं। राउत, जो पूरी बैठक के दौरान मौजूद थे, ने जोर देकर कहा कि पार्टी प्रमुख ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने यह नहीं कहा कि जो लोग जाना चाहते हैं वे चले जाएं, और वे कभी ऐसी बात नहीं कहेंगे। ठाकरे के नेतृत्व करने के तरीके का बचाव करते हुए राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई नेता नहीं है जो शिवसेना प्रमुख जितने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलता हो।

न कोई ट्रस्टी बचे, न अधिकारी, अखिलेश का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले-

बीजेपी के हर कॉरिडोर और चौड़ीकरण के पीछे बड़ा घोटाला, न्यायिक जांच हो

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की कॉरिडोर और चौड़ीकरण योजनाओं में घपले-घोटाले का आरोप लगाते हुए मंगलवार को बहुसदस्यीय न्यायिक जांच की मांग की। सपा प्रमुख ने यह मांग राम मंदिर के दान पात्र और वित्तीय प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच शुरू होने के बाद उठाई है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भाजपा सरकार के बनाए हर कॉरिडोर और चौड़ीकरण की योजना के पीछे जो घपला-

घोटाला है, उसकी बहुसदस्यीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, इसमें संलिप्त किसी ट्रस्टी, किसी समिति के सदस्य या किसी प्रशासनिक एवं विकास प्राधिकरण के अधिकारी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इतने बड़े घोटाले इन सभी की मिलीभगत से ही संभव होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में इन परियोजनाओं से जुड़े रहे सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों तथा इनमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले लोगों की कथित रूप से अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों और अकूत धन-संपदा की भी जांच होनी चाहिए। यह जांच आम जनता, ईमानदार पत्रकारों और विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों की निगरानी में कराई जानी चाहिए। यादव ने पोस्ट के साथ 31 सेकंड का एक वीडियो भी साझा किया। वीडियो पर लिखा है, अयोध्या- साल 1940 में स्थापित शिव मंदिर पर चला बुलडोजर। वीडियो में एक मंदिर जैसी संरचना को बुलडोजर से तोड़ते हुए दिखाया गया है।

राजौरी में एलओसी के पास धमाके, जेसीओ सहित 4 जवान घायल

राजौरी । मंगलवार को राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में एक रहस्यमयी धमाके में सेना के 4 जवान घायल हो गए। घायल जवानों में एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक यह घटना लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कलाल इलाके में हुई, जब सैनिक एक फॉरवर्ड लोकेशन पर ऑपरेशनल ड्यूटी पर थे। धमाके की असल वजह का तुरंत पता नहीं चल सका है और घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। घायल जवानों को तुरंत घटनास्थल से निकालकर इलाज के लिए मेडिकल सेंटर ले जाया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सुरक्षाबलों ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है, जबकि अधिकारी धमाके के पीछे के सभी संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं। आगे की जानकारी का इंतजार है।

ट्रंप की मौजूदगी में पीएम मोदी ने उठाया नाविकों की मौत का मुद्दा

एवियन । जी7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अमेरिकी सैन्य हमलों में मारे गए भारतीय नाविकों का मुद्दा उठाया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही बैठे थे। जी7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हुए कहा कि हालिया संघर्ष ने क्षेत्र के कई मित्र देशों को जान-माल का भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष ने पश्चिम एशिया में हमारे मित्र देशों को जान-माल का नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री व्यापार बाधित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। कई भारतीय नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है।

वैश्विक समुद्री व्यापार पर क्या बोले पीएम मोदी?

समुद्री व्यापार में नाविकों की भूमिका का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित बने रहें और नाविक बिना किसी भय के अपना काम कर सकें। जी7 शिखर सम्मेलन में नए साझेदारी संबंधों का निर्माण और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की पुनर्बहाली विषय पर आयोजित आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यवस्था में भरोसे को सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया पहले से कहीं अधिक आपस में जुड़ी और एक-दूसरे पर निर्भर है।

दुनिया के देशों के बीच भरोसे की कमी - प्रधानमंत्री

उन्होंने कहा, किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि अब केवल उसकी सीमाओं के भीतर तय नहीं होती। सफल साझेदारियां केवल विश्वास और विश्वसनीयता की नींव पर ही खड़ी की जा सकती है। आज सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति कोई खनिज, तकनीक या बाजार नहीं, बल्कि आपसी विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशों को यह भरोसा होना चाहिए कि तकनीक, आपूर्ति श्रृंखलाएं और वैश्विक संस्थाएं दबाव या बहिष्कार का साधन बनने के बजाय सामूहिक हितों की सेवा करेंगी। उन्होंने कहा, भरोसा होना चाहिए कि तकनीक और सप्लाई चेन का इस्तेमाल हथियार के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक भलाई के लिए होगा। भरोसा होना चाहिए कि विकास के अवसर कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। भरोसा होना चाहिए कि वैश्विक संस्थाएं सभी देशों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होंगी। कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस संकट ने वैश्विक एकजुटता की कमजोरियों को उजागर कर दिया था। उन्होंने कहा, कई पीढ़ियों के योगदान से दशकों में बना विश्वास अब कमजोर पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी ने हमें आईना दिखाया और यह उजागर किया कि विश्वास और एकजुटता के दावे कई बार कितने खोखले साबित हुए।

जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कई राष्ट्राध्यक्षों संग की द्विपक्षीय बैठक

प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी जी7 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आई, जहां विश्व नेताओं ने आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहित कई वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। इससे पहले दिन में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से संक्षिप्त मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और कुछ देर बातचीत भी की।

पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी समेत कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की।